नंदिग्राम टाईम्स

RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD

Saturday 20th December 2025 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 234 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

थरूर ने बांग्लादेशी नेता के 'सेवन सिस्टर्स' बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया, शांति व शांति बहाली की अपील

नई दिल्ली: बांग्लादेश में जारी तनाव के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बांग्लादेशी नेता द्वारा भारत के पूर्वोत्तर के 'सेवन सिस्टर्स' राज्यों से जुड़े भड़काऊ बयान की कड़ी निंदा की है। थरूर ने कहा कि ऐसे "इररेस्पॉन्सिबल" और "मूर्खतापूर्ण" बयानों से क्षेत्रीय शांति पर गंभीर असर पड़ रहा है और इसके लिए बांग्लादेश सरकार को कदम उठाना चाहिए।

थरूर ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में पूछा, "वह कौन होता है जो इस तरह की बातें करता है?" — इशारा उस बयान की ओर जिसमें नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के हसनत अब्दुल्ला ने कहा था कि बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर के सात राज्यों को अलग कर सकता है और अलगाववादी शक्तियों को ठिकाना दे सकता है। उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत उम्मीद करता है कि ढाका की राजनीति में ऐसी पंक्तियाँ नियंत्रण में रहें ताकि दोनों देशों के बीच पारंपरिक हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। थरूर ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के समर्थन के लिए कदम उठाएगा।

बीच में बांग्लादेश में एक छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़की, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोगों के पास भी प्रदर्शन किए। राजशाही में एक हिंदू युवक पर ईशनिंदा के आरोप में हमला और उसके बाद उसकी लिंचिंग की भयावह घटना भी सामने आई, जिससे तनाव और बढ़ गया है। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर सुरक्षा स्थितियों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि थरूर ने दोनों देशों के हितों में संयम और समझौते का आह्वान किया है।

5G टेलीकॉम | सर्विसेज जैसे वाला इंटरनेट संपर्क प्रदान करने में सक्षम किया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम रोका, यूनिवर्सिटी में गोलीबारी के बाद उठाया कदम, भारतीयों की बढ़ेगी टेंशन!

वॉशिंगटन | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। लॉटरी पर रोक की वजह हाल ही में ब्राउन यूनिवर्सिटी और MIT में हुई गोलीबारी बताई गई है। गोलीबारी के आरोपी को ग्रीन कार्ड प्रोग्राम का लाभार्थी बताया जा रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने बताया कि ट्रंप के निर्देश पर उन्होंने यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से इस प्रोग्राम को रोकने के लिए कह दिया है। इससे भारतीय भी बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे।

ब्राउन विश्वविद्यालय और एमआईटी में गोलीबारी की घटना का संदिग्ध कथित तौर पर ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम का लाभ उठाकर अमेरिका आया था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला लिया है। क्रिस्टी नोएम ने गोलीबारी की घटना के मुख्य संदिग्ध पुर्तगाली नागरिक क्लाउडियो नेवेस वैलेंते पर बात करते हुए कहा कि इस घृणित व्यक्ति को हमारे देश में कभी एंट्री नहीं दी जानी चाहिए थी।

नेवेस पर गोलीबारी का शक

48 साल के नेवेस वैलेंते पर ब्राउन विश्वविद्यालय गोलीबारी में शामिल होने का संदेह है। इस घटना में दो छात्रों की मौत हुई और नौ लोग घायल हुए। गोलीबारी की दूसरी घटना में एमआईटी के एक प्रोफेसर की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार शाम नेवेस वैलेंते ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

नेवेस वैलेंते ने साल 2000 में छात्र वीजा पर ब्राउन विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू की थी। साल 2017 में वैलेंते को विविधता आप्रवासी वीजा मिला। इसके बाद उसे कानूनी रूप से स्थायी निवास का दर्जा हासिल हो गया। यह साफ नहीं हो सका कि 2001 से 2017 में वीजा प्राप्त करने के बीच वह कहां रह रहा था।

ग्रीन कार्ड लॉटरी

वीजा कार्यक्रम के तहत हर साल लॉटरी से 50,000 की संख्या तक ग्रीन कार्ड उन देशों के लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इस साल, 2025 में अमेरिका में दो करोड़ लोगों ने वीजा लॉटरी कार्यक्रम के लिए आवेदन किया था। इनमें विजेताओं के पार्टनर सहित 1,31,000 लोगों का चयन हुआ।

लॉटरी विजेताओं को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद दूतावासों में उनका साक्षात्कार लिया जाता है। इस कार्यक्रम में भारतीय भी बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले से भारतीयों की भी मुश्किल निश्चित तौर पर बढ़ने जा रही है।

केंद्र का बयान – AQI और फेफड़ों की बीमारी के बीच सीधा वैज्ञानिक लिंक नहीं

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि हवा की खराब गुणवत्ता (उच्च AQI) और फेफड़ों की बीमारियों के बीच कोई निर्णायक वैज्ञानिक डेटा नहीं है, जो दोनों के बीच सीधा संबंध साबित करे। राज्यसभा में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उत्तर देते हुए स्वीकार किया कि वायु प्रदूषण सांस संबंधी बीमारियों के लिए ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन उपलब्ध शोध "सीधे कारण-प्रभाव" को स्थापित नहीं करता। प्रश्न भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने दिल्ली-NCR में लंबे समय तक खराब AQI के संपर्क से फेफड़ों की गंभीर बीमारियों जैसे फाइब्रोसिस, COPD आदि के बढ़ते मामलों के बारे में पूछा था।

सरकार ने बताया कि वह प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और स्वच्छ हवा के लिए विभिन्न उपायों पर काम कर रही है, हालांकि सीधा सबूत अभी तक नहीं मिला।

पश्चिम बंगाल जा रहे पीएम मोदी, राज्य के लोगों को देंगे 3200 करोड़ रुपये की सौगात

मुंबई | नई दिल्ली : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 3,200 करोड़ रुपये की लागत वाले दो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस दौरे को लेकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा मैं कल, 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच रहने का इंतजार कर रहा हूं। सुबह करीब 11:15 बजे, मैं नदिया जिले के रानाघाट में एक पब्लिक प्रोग्राम में शामिल होऊंगा, जहां 3200 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट कामों का या तो उद्घाटन किया जाएगा या उनकी नींव रखी जाएगी।

उद्घाटन

इन परियोजनाओं का होगा पीएम मोदी NH-34 के बाराजागुली-कृष्णानगर सेक्शन के 66.7 किमी 4-लेन हिस्से का उद्घाटन करेंगे। साथ ही, H-34 के बारासात-बाराजागुली सेक्शन को 4-लेन बनाने के लिए नींव रखना। इससे कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में NH-34 के 66.7 किलोमीटर लंबे बाराजागुली - कृष्णानगर सेक्शन की 4-लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। वह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले में NH-34 के 17.6 किलोमीटर लंबे बारासात-बाराजागुली सेक्शन की 4-लेन सड़क की आधारशिला भी रखेंगे।

क्यों अहम हैं ये प्रोजेक्ट?

ये प्रोजेक्ट कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक ज़रूरी कनेक्टिंग लिंक का काम करेंगे। इनसे यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम हो जाएगा। इससे बिना रुकावट ट्रैफिक फ्लो के लिए गाड़ियों की तेज और आसान आवाजाही सुनिश्चित होगी। साथ ही, गाड़ियों के चलाने का खर्च कम होगा। इससे कोलकाता और पश्चिम बंगाल के दूसरे पड़ोसी ज़िलों के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे और पूरे क्षेत्र में टूरिज्म के विकास को गति देंगे।

हमारी संसद की प्रासंगिकता कम हो रही... ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक, कपिल सिब्बल क्यों कह रहे यह बात

हमारी संसद की प्रासंगिकता कम हो रही...

नई दिल्ली : राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को दावा किया कि संसद की प्रासंगिकता ''धीरे-धीरे कम हो रही है'' क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है और वे सिर्फ उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मौजूदा समय के लिए अप्रासंगिक हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए ''बेहद खतरनाक'' है क्योंकि संसद में वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है।

हमारी संसद की प्रासंगिकता कम हो रही

निर्दलीय सांसद ने कहा, मुझे लगता है कि हमारी संसद की प्रासंगिकता धीरे-धीरे कम हो रही है। अब कम बैठकें होती हैं और लोग सोचते हैं कि वहां कुछ नहीं होता है। यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है। इसके बजाय, ऐसे विषय उठाए जाते हैं जो आज के समय के लिए अप्रासंगिक हैं।'

कम बैठकों से चर्चा के लिए समय नहीं मिल रहा

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि शीतकालीन सत्र एक से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, जिसके दौरान 15 बैठकें हुईं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''जब हम पहले संसद में थे, तो शीतकालीन सत्र 20 नवंबर को शुरू होता था। 2017 में 13 बैठकें हुईं, 2022 में 13 बैठकें हुईं, 2023 में 14 बैठकें हुईं। अगर यही जारी रहा तो जो चर्चा होनी चाहिए वह नहीं हो सकेगी। ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोगों को संसद की ज्यादा परवाह नहीं है।

सिब्बल ने कहा कि विपक्ष एक दिसंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा चाहता है क्योंकि एसआईआर आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार ने शर्त रख दिया कि पहले वंदे मातरम् पर चर्चा होगी। उन्होंने दावा कि संसद की प्रासंगिकता धीरे-धीरे कम हो रही है।

बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई, भारतीय मिशन के बाहर भी प्रदर्शन

ढाका/चटगांव: बांग्लादेश में प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देशभर में भारी अशांति फैल गई है। हादी, इंकिलाब मंच के प्रवक्ता और 2024 के विद्रोही आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे, जिन्हें 12 दिसंबर को ढाका में गोली मार दी गई थी। गंभीर हालत में उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे समर्थकों में रोष फैल गया।

मौत की खबर मिलते ही राजधानी ढाका सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अवामी लीग, अंतरिम सरकार और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। शाहबाग चौक पर रैलियाँ निकाली गईं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई।

हिंसा तीव्र रूप ले गई और देश के दो सबसे बड़े समाचार पत्रों — 'प्रथोम आलो' तथा 'द डेली स्टार' — के कार्यालयों में आग लगा दी गई, जिससे पत्रकार और स्टाफ सुरक्षित रूप से बचाए गए। विरोध का विस्तार होते हुए चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर भी पथराव और तोड़फोड़ देखी गई, पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

मौजूदा तनाव के बीच, बांग्लादेश की interim सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और फैसल कौन थे के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, हिंसा ने देश के राजनीतिक माहौल को और अस्थिर कर दिया है, जिससे सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।

लाल किला ब्लास्ट केस में NIA कस्टडी बढ़ी, मुख्य आरोपी बिलाल नसीर मल्ला 26 दिसंबर तक एजेंसी हिरासत में

नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में शुक्रवार को आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला की एनआईए हिरासत को सात दिनों के लिए बढ़ा दिया। इसके अलावा अदालत ने बम विस्फोट करने वाले उमर-उन-नबी को पनाह देने वाले फरीदाबाद निवासी शोएब को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

शोएब, बिलाल की कोर्ट में पेशी

जांच एजेंसी ने शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शोएब और बिलाल को पटियाला हाउस अदालत में पेश किया। दोनों को 15 दिसंबर को चार दिनों के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की हिरासत में भेजा गया था,

जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी। मीडियाकर्मियों को अदालत की कार्यवाही को कवर करने से रोक दिया गया था।

दोनों आरोपियों को प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने जांच एजेंसी को नसीर को हिरासत में लेकर सात और दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति दी। वहीं, शोएब को 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

फरीदाबाद निवासी शोएब ने की थी मदद

एनआईए के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने पहले कहा था कि एजेंसी ने हरियाणा के फरीदाबाद के धौज निवासी शोएब को दिल्ली विस्फोट से पहले 'आतंकवादी' उमर-उन-नबी को रसद संबंधी सहायता प्रदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने डॉ. नसीर बिलाल मल्ला को साजिश का मुख्य आरोपी बताते हुए नौ दिसंबर को दिल्ली में गिरफ्तार किया था।

एनआईए की जांच के अनुसार, नसीर ने उमर-उन-नबी को रसद संबंधी सहायता प्रदान करके जानबूझकर उसे शरण दी थी। एनआईए ने इस मामले में पहले ही नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें तीन और डॉक्टर डॉ. मुज़म्मिल गनाई, डॉ. अदील राथर, डॉ. शाहीन सईद और धार्मिक उपदेशक मौलवी इरफान शामिल हैं।

सफेदपोश टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़

यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किए गए एक 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। दस नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे। यह कार उमर उन नबी चला रहा था। घटना में दो दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। कार आमिर राशिद अली के नाम से पंजीकृत पाई गई थी।

शीतकालीन अधिवेशन में ग्रामीण रोजगार पर मंथन: मनरेगा के भविष्य की बहस

संपादकीय... |

संसद के शीतकालीन अधिवेशन में इस बार यदि किसी एक विषय ने सरकार और विपक्ष के बीच सबसे तीखी बहस को जन्म दिया, तो वह था ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का भविष्य और उसमें प्रस्तावित बदलाव। यह मुद्दा केवल एक सरकारी योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।

मनरेगा, जिसे वर्ष 2005 में लागू किया गया था, ग्रामीण भारत में रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाली देश की सबसे बड़ी सामाजिक-आर्थिक योजना रही है। इस योजना के अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का मजदूरी-आधारित रोजगार सुनिश्चित करने का प्रावधान है। कोरोना महामारी, सूखा, बाढ़ और महंगाई के दौर में इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरकार का पक्ष: सुधार और दक्षता की जरूरत

शीतकालीन अधिवेशन में सरकार की ओर से यह तर्क रखा गया कि मनरेगा को मौजूदा समय की जरूरतों के अनुरूप सुधारों और पुनर्संरचना की आवश्यकता है। सरकार का कहना है कि योजना में तकनीक का अधिक उपयोग, परिसंपत्ति-आधारित कार्यों पर जोर और कौशल विकास को जोड़कर इसे केवल “रोजगार योजना” से आगे बढ़ाकर “आजीविका सृजन का माध्यम” बनाया जाना चाहिए।

सरकारी पक्ष ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ राज्यों में भुगतान में देरी, फर्जी जॉब कार्ड, और कार्य की गुणवत्ता जैसे मुद्दे सामने आए हैं। ऐसे में पारदर्शिता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और निगरानी तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य हो गया है। सरकार का दावा है कि प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य मनरेगा को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाना है।

विपक्ष का विरोध: अधिकारों में कटौती की आशंका

वहीं विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। विपक्षी दलों का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों का संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव यदि रोजगार की कानूनी गारंटी को कमजोर करता है, तो वह ग्रामीण भारत के साथ अन्याय होगा।

विपक्ष ने यह सवाल भी उठाया कि जब महंगाई बढ़ रही है, ग्रामीण आय पर दबाव है और बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, तब मनरेगा के बजट, कार्य दिवसों या स्वरूप में बदलाव क्यों किया जा रहा है। उनका तर्क है कि सरकार को योजना को और मजबूत करने की जरूरत है, न कि उसके दायरे को सीमित करने की।

बड़ी तस्वीर: विकास बनाम सुरक्षा की बहस

असल में मनरेगा पर हुई यह बहस विकास और सामाजिक सुरक्षा के संतुलन की बहस है। एक ओर सरकार दीर्घकालीन ग्रामीण विकास, कौशल और आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष तत्काल रोजगार सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की रक्षा पर जोर दे रहा है।

यह भी सच है कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरी को न्यूनतम सहारा दिया है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बदलती अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों को केवल मजदूरी-आधारित रोजगार से आगे ले जाने की चुनौती भी सामने है।

निष्कर्ष

शीतकालीन अधिवेशन में मनरेगा पर हुई चर्चा यह स्पष्ट करती है कि ग्रामीण रोजगार आज भी राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि सुधार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जाए। मनरेगा में पारदर्शिता, समय पर भुगतान और गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी सुधार से ग्रामीण गरीबों के रोजगार के अधिकार पर आंच न आए।

ग्रामीण भारत की मजबूती के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है—और मनरेगा पर हुई यह बहस उसी सच्चाई की याद दिलाती है।

IND vs SA | हार्दिक-तिलक के बाद बुमराह-वरुण की जुगलबंदी का कमाल

IND vs SA: हार्दिक-तिलक के बाद बुमराह-वरुण की जुगलबंदी का कमाल, टीम इंडिया ने जीत के साथ किया साल का अंत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली | साउथ अफ्रीका ने पूरे भारत दौरे पर शानदार खेल दिखाया। उसने पहले दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को मात दे इतिहास रचा। इसके बाद वनडे में भी उसने दमदार खेल दिखाया लेकिन सीरीज नहीं जीत सकी। टी20 सीरीज में भी वह पीछे थी और आखिरी मैच जीत सीरीज का अंत बराबरी के साथ करने के लिए उसने पूरी कोशिश की जिसमें वह सफल नहीं रही। टीम इंडिया ने शुक्रवार को पांचवें टी20 में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हरा सीरीज 3-1 से अपने नाम की।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारियों के दम पर 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 231 रन बनाए। साउथ अफ्रीका क्विंटन डिकॉक के तूफानी पारी के दम पर जीत हासिल करती दिख रही थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह और फिर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी ने भारत की वापसी कर दी। साउथ अफ्रीका 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 201 रन ही बना सकी।

भारत ने पहला मैच अपने नाम किया था तो साउथ अफ्रीका हिस्से दूसरे मैच में जीत आई थी। तीसरे मैच को जीत टीम इंडिया ने 2-1 की बढ़त ले ली। लखनऊ में चौथा मैच खराब मौसम के कारण हो नहीं सका था और इसलिए साउथ अफ्रीका के पास सीरीज जीत का मौका नहीं था। वह आखिरी मैच जीत सीरीज बराबरी पर ही खत्म कर सकती थी जो नहीं कर सकी।

साउथ अफ्रीका की तूफानी शुरुआत

डीकॉक ने अर्शदीप सिंह द्वारा फेंके गए पहले ही ओवर में रनों की बारिश कर दी। यहां से उन्होंने जो तूफान शुरू किया वो भारत के लिए परेशानी बन गया। पावरप्ले के छह ओवरों में साउथ अफ्रीका ने बिना विकेट खोए 67 रन बनाए थे। रीजा हेंड्रिग्स को रन बनाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन डीकॉक आसानी से रन बना रहे थे। रीजा की पारी का अंत वरुण ने सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर कर दिया। वह 12 गेंदों पर 13 रन ही बना सके।

लेकिन इसके बाद डीकॉक ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। इस बीच डीकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 117 रन था।

पलट गया मैच

10वें ओवर के बाद हुए ड्रिंग्स ब्रेक में सारी कहानी बदल गई। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने डिकॉक की पारी का अंत कर दिया। वह 35 गेंदों पर नौ चौके और तीन छक्कों की मदद से 65 रन बनाने में सफल रहे। पांड्या ने फिर 12वें ओवर की पहली गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस को भी आउट कर दिया। उन्होंने 17 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 31 रन बनाए।

बुमराह के बाद वरुण ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को परेशानी में डाल दिया। वरुण ने 13वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दो लगातार विकेट लेकर मेहमान टीम की कमर तोड़ दी। उन्होंने पहले एडेन मार्करम (6) और फिर डोनावान फरेरा को आउट कर भारत को मजबूत कर दिया।

अर्शदीप ने फिर 15वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर को (18) को आउट कर भारत को और मजबूत कर दिया। वरुण ने जॉर्ज लिंडे को आउट कर भारत को सातवीं सफलता दिला दी। 17वें ओवर की पहली गेंद पर संजू की सूझबूझ से भारत को मार्को यानसेन की विकेट भी मिल गया और यहां से भारत की जीत पक्की हो गई थी। साउथ अफ्रीका ने यहां से कोई और विकेट तो नहीं खोया लेकिन वो जरूरी रन भी नहीं बना सकी।

भारत के लिए वरुण ने चार विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लिए।

पांड्या-तिलक की विस्फोटक साझेदारी से भारत मजबूत

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने संभाल लिया। शुरुआती विकेट गिरने के बाद दोनों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया।

12.1 ओवर में 115 रन पर हार्दिक के क्रीज पर आते ही मैच का रुख बदला। पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाले पांड्या और तिलक ने 17 गेंदों में 55 रन जोड़ दिए। हार्दिक ने मात्र 16 गेंदों में अर्धशतक लगाकर टी-20 अंतरराष्ट्रीय का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ा और अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा।

हार्दिक ने 25 गेंदों में पांच छक्कों और पांच चौकों की मदद से 63 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रन की पारी खेली। दोनों की इस धमाकेदार बल्लेबाजी से भारत ने साउथ अफ्रीका पर दबदबा बना लिया।

WORLD NEWS | बांग्लादेश में यूं ही नहीं मचा है बवाल

बांग्लादेश में यूं ही नहीं मचा है बवाल, पाकिस्तानी ISI पूरे प्लान के साथ बना रही 'पूर्वी मोर्चा', भारत की चिंता कितनी गंभीर

● NEWS AGENCY

ढाका: बांग्लादेश के कई बड़े शहर छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा की चपेट में है। खासतौर से राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। बांग्लादेश में बीते साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस ने भारत से दूरी बनाते हुए पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर किए हैं। बांग्लादेश में लगातार अस्थिरता के पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के ढाका में बढ़ते प्रभाव से जोड़ा जा रहा है।

न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि ढाका में ISI बहुत गहरे और सुनियोजित तरीके से प्रभाव जमा रहा है। पंद्रह साल में पहली बार पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का बांग्लादेश के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर सीधा असर डाल रही है। ढाका-इस्लामाबाद धुरी के बढ़ते गठजोड़ पर नई दिल्ली की चिंता भी बढ़ रही है।

ISI का 'ढाका सेल'

भारत और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सबसे चिंताजनक बात ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर एक समर्पित ISI स्पेशल सेल है। CNN-News18 का दावा है कि इस यूनिट में उच्च पदस्थ सैन्य और इंटेलिजेंस अधिकारियों की एक टीम है। इसमें एक ब्रिगेडियर, दो कर्नल, चार मेजर और पाकिस्तान की नौसेना और वायु सेना के कई अधिकारी शामिल हैं। इस सेल को अक्टूबर में पाकिस्तान सेना के सीनियर अफसर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ढाका के चार दिवसीय दौरे के दौरान कई बैठकें कीं। इन बैठकों के परिणामस्वरूप एक संयुक्त इंटेलिजेंस-शेयरिंग तंत्र बना। इसका मकसद बंगाल की खाड़ी की निगरानी कहा गया है लेकिन असल में यह भारत की पूर्वी सीमाओं की निगरानी के लिए है।

ISI का कट्टरपंथी मिशन

खुफिया विश्लेषकों का कहना है कि बांग्लादेश में ISI का खास मिशन युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ मोड़ना है। इसमें जमात-ए-इस्लामी और इंकलाब मंच जैसे समूहों को जरिया बनाया जा रहा है। 18 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद फैली अशांति में भी ISI का असर देखा गया है।

पाकिस्तानी ISI पूरे प्लान के साथ बना रही 'पूर्वी मोर्चा',

पर्यवेक्षकों का तर्क है कि हादी की मौत के बाद ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव में सहायक उच्चायोग पर हमले हुए हैं। इसले बांग्लादेश में बढ़ते भारत विरोध को देखा जा सकता है। अस्थिरता को बढ़ावा देकर कट्टरपंथी तत्व अपना प्रभाव मजबूत कर रहे हैं। ढाका में बैठी यूनुस सरकार इसे रोकने में अनिच्छुक दिखी है।

भारत की बढ़ी चिंता

भारत ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के दखल पर अपनी चिंता को कई बार रखा है। 19 नवंबर को दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव समिट के दौरान NSA अजीत डोभाल ने बांग्लादेशी एनएसए खलीलुर्रहमान के साथ कथित तौर पर ढाका में ISI सेल का मुद्दा उठाया था। ढाका में पाकिस्तानी दखल को भारत की नेबर फर्स्ट नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सीधा खतरा माना जा रहा है।

महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ

नंदिग्राम टाईम्स
RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD
Saturday 20th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 234 , पृष्ठ 03

बॉम्बे हाईकोर्ट से NCP नेता माणिकराव कोकाटे को बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली पर सजा पर रोक नहीं

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी (1995) मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई और उन्हें ₹1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी है, जिससे उनकी तत्काल गिरफ्तारी टल गई है। हालांकि, अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे मामला अभी भी गंभीर बना हुआ है।

यह मामला 1995 का है, जब कोकाटे और उनके भाई पर आरोप था कि उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत सरकारी फ्लैटों को धोखाधड़ी और दस्तावेजों में जालसाजी करके हासिल किया। प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर उच्च न्यायालय ने यह माना कि आरोपों में गंभीरता है, इसलिए सजा पर रोक का अनुरोध मंजूर नहीं किया गया।

कोकाटे को नासिक सेशंस कोर्ट ने दो साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी है, जिससे वे गिरफ्तारी से बच गए हैं। हालांकि उनकी दोषसत्ता बरकरार है और इसलिए उनकी एमएलए सदस्यता तथा राजकीय पद पर कायम रहने की स्थिति अभी विवाद के अधीन है, जिसे आगे के न्यायिक आदेश तय कर सकते हैं।

राजनीतिक मोर्चे पर यह फैसला बड़ा महत्व रखता है और इसके चलते कोकाटे के लिए राजनीतिक भविष्य, पद और जनप्रतिनिधि अधिकारों पर बहस जारी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार विधानसभा स्पीकर को एमएलए सदस्यता से संबंधित निर्णय लेना होगा।

BMC Election | अजित पवार महायुति और शरद पवार MVA के साथ चाहते हैं गठबंधन?

BMC Election: अजित पवार महायुति और शरद पवार MVA के साथ चाहते हैं गठबंधन, बीएमसी चुनाव में कहां तक पहुंची चर्चा?

मुंबई | राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने स्थापना के बाद से अब तक मुंबई में अपनी मजबूर उपस्थित दर्ज नहीं करा पाई इसलिए वह किसी न किसी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ते आ रही है। इस बार अजित पवार महायुति के साथ और शरद पवार उद्धव सेना और मनसे के साथ गठबंधन कर लड़ना चाहते हैं। एनसीपी (एपी) प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बताया कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है और बीजेपी के प्रभारी नेताओं से भी चर्चा चल रही है, इसलिए मुंबई के साथ अन्य महानगरपालिका चुनाव महायुति के रूप में लड़ने की रणनीति तय की जाएगी। महाविकास आघाडी के साथ शरद पवार की एनसीपी के गठबंधन के बारे में सिल्वर ओक पर बैठक हो रही है।

नवाब मलिक को लेकर बीजेपी में भारी विरोध

दरअसल, सत्ताधारी महायुति में अजित पवार की पार्टी के नेता नवाब मलिक को लेकर बीजेपी में भारी विरोध है। बीजेपी के कई नेताओं ने साफ कहा है कि उन्हें नवाब मलिक नहीं चाहिए। मलिक के साथ वे चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, बैठक करने की तो दूर की बात है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम का कहना है कि अजित पवार की एनसीपी से गठबंधन के बारे में पार्टी नेताओं से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले। रही बात अजित पवार की पार्टी से गठबंधन की तो यह निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है।

अजित पवार की मंशा क्या?

बताया जाता है कि अजित पवार चाहते हैं कि बीएमसी में वे महायुति के साथ लड़ेंगे तो ही उन्हें फायदा होगा, वर्ना बीएमसी में उनकी डगर बहुत कठिन होगी। बीजेपी के विरोध के बाद पार्टी मलिक की बजाय उनकी विधायक बेटी सना को आगे लाना चाहती है। इससे बीजेपी के विरोध की धार कम होगी और गठबंधन भी आसन हो जाएगी। शरद पवार क्या चाहते हैं?

इधर, शरद पवार उद्धव सेना और मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए बातचीत चल रही है। जल्द ही इसके सकारात्मक नतीजे आने की संभावना है। बीएमसी में एनसीपी अब तक अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई है। गठबंधन के बिना उनकी जीत आसान है।

मुंबई में दोनों ही एनसीपी का कुछ खास प्रभाव नहीं

राजनीति विशेषज्ञ कहते है कि मुंबई में दोनों ही एनसीपी का कुछ खास प्रभाव नहीं है इसलिए उन्हें बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना उनके लिए कठिन है इसलिए अजित पवार चाहते हैं कि महायुति के साथ लड़े और शरद पवार जुगाड़ कर रहे हैं कि वे उद्धव और मनसे के साथ मिलकर लड़े।

भायंदर पूर्वे में तेंदुए का हमला, रिहायशी सोसायटी में घुसकर 3 लोग घायल — हड़कंप

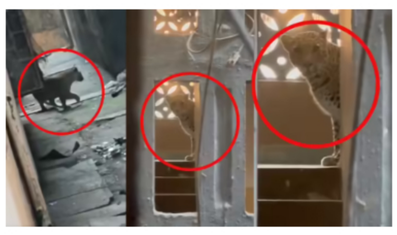

भायंदर (ठाणे): भायंदर ईस्ट के परिजात सोसायटी में शुक्रवार सुबह एक तेंदुआ अचानक घुस आया और तालाव रोड इलाके में अफरा-तफरी मचा दी, जिससे स्थानीय लोगों में भय व्याप्त हो गया। तेंदुए ने कई राहगीरों और सोसायटी के निवासियों पर हमला किया, जिससे कम-से-कम चार लोग घायल हुए और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पशु के भयंकर रूप से पेश आने के कारण आसपास के लोग घरों के अंदर सुरक्षित रहने को कहा गया। घटना के बाद वन विभाग, पुलिस और अग्निशमन दल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए घंटों चली कार्रवाई के बाद इसे एक फ्लैट में कोने में फँसा कर ट्रैंक्विलाइज़र डार्ट से बेहोश करके सुरक्षित पकड़ा गया।

सोसायटी और आसपास के क्षेत्र में पुलिस तथा वन विभाग ने तत्काल सतर्कता बढ़ा दी है और निवासियों से कहा गया है कि वे बाहर न निकलें। घायल लोग स्थिर स्थिति में हैं और उनकी चिकित्सा जारी है। अधिकारी अब तेंदुए को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर ले जाने और उसका पुनर्वास कराने की तैयारी कर रहे हैं। यह अप्रत्याशित घटना शहरी इलाकों में वन्यजीवों के प्रवेश की चिंताओं को उजागर करती है और स्थानीय प्रशासन तथा वन विभाग द्वारा और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

मानखुर्द-शिवाजी नगर में सपा के गढ़ में AIMIM की एंट्री से बिगड़ा खेल, मुस्लिम वोटों का समीकरण बदल सकता है

मुंबई | मानखुर्द-शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र के मनपा चुनावों के लिए इस बार खास नजरों में है, क्योंकि परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी (सपा) का यह गढ़ रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की एंट्री से राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। आगामी मुंबई नगर निगम (मनपा) चुनाव से पहले यहां सपा की मजबूत पकड़ पर AIMIM चुनौती दे रही है, जिससे मुकाबला पहले से अधिक कांटे का बन गया है।

यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल है, जहाँ लगभग 58% मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि बाकी 42% अन्य समुदायों के मतदाता हैं। ऐतिहासिक रूप से सपा ने 2017 के मनपा चुनाव में यहां 5 में से कई सीटें जीतें, लेकिन हाल के वर्षों में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है।

राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी AIMIM के प्रत्याशी अतीक शेख ने लगभग 42,027 वोट हासिल किए, जो कि सपा विधायक अबू आसिम आजमी को मिले 54,780 वोटों के मुकाबले कम थे, लेकिन यह आंकड़ा बताता है कि AIMIM धीरे-धीरे अपनी पैठ बना रही है। सपा के लिए बड़ी समस्या तब पैदा हुई जब दो पूर्व नगरसेवक आयशा रफीक शेख और अख्तर कुरैशी ने पार्टी छोड़कर शिवसेना (शिंदे गुट) का दामन थाम लिया, जिससे सपा की जमीनी शक्ति पर प्रभाव पड़ा। विश्लेषकों का कहना है कि यदि मनपा चुनाव में मुस्लिम वोटों का विभाजन इसी तरह से होता है, तो इसका सीधा फायदा AIMIM और महायुति गठबंधन को हो सकता है, जिससे सपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बार का मुकाबला इसलिए बेहद दिलचस्प और अनिश्चित माना जा रहा है।

कुल मिलाकर मानखुर्द-शिवाजी नगर इलाके में इस चुनावी सीज़न में सपा का परंपरागत प्रभुत्व चुनौती में है और AIMIM की सक्रिय भागीदारी से स्थानीय राजनीति का खेल बदलता हुआ दिख रहा है।

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला — विशेष शालाओं में 'दिशा पोर्टल' अनिवार्य

मुंबई: बौद्धिक अक्षम (ऑटिस्टिक) विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता और एकसमानता सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 'दिशा' विशेष अध्ययन कार्यक्रम को लागू करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे के आदेश के मुताबिक, अब सभी विशेष शालाओं को 'दिशा' पोर्टल पर ऑनबोर्ड करना, मुख्याध्यापकों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और व्यक्तिगत शिक्षा व थेरपी कार्यक्रम बनाना आवश्यक होगा। अधिकारियों ने कहा कि इस अभ्यासक्रम की प्रभावी अंमलबजावणी नहीं करने वाली शालाओं पर राज्य अनुदान रोके जाने या पंजीकरण रद्द किए जाने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिशाबद्ध मूल्यांकन, बहुसंवेदी अध्यापन पद्धतियों का उपयोग और नियमित समीक्षा भी अनिवार्य होगी। इससे विद्यार्थियों की प्रगति का वार्षिक एवं मध्य सत्र में मूल्यांकन कर पेरेंट्स को रिपोर्ट दी जाएगी। जो शालाएँ 'दिशा' कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करेंगी, उन्हें "दिशा अंमलबजावणी शाला" के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 से विद्यार्थियों और शिक्षकों को दिशाबद्ध पुस्तिकाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँगी। प्रशासन ने यह कदम विशेष शिक्षा के मानकीकरण और गुणवत्तापूर्ण सीख सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है।

यवतमाळ चुनाव: सीएम फडणवीस ने रिकॉर्डेड कॉल से मतदाताओं को किया भाजपा उम्मीदवार के लिए मतदान का आग्रह

यवतमाळ (महाराष्ट्र): यवतमाळ नगर परिषद चुनाव के अंतिम प्रचार दिवस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक असामान्य अभियान छेड़ा है। उन्होंने मतदाताओं को रिकॉर्डेड फोन कॉल के माध्यम से सीधे संबोधित किया और भाजपा उम्मीदवारों तथा उनके पक्ष में मतदान का आग्रह किया है। कॉल में फडणवीस का संदेश होता सुनाई देता है, "हॅलो, मी मुख्यमंत्री बोलतोय...", जिससे प्राप्तकर्ता को ऐसा अनुभव होता है कि सीएम खुद उनसे बात कर रहे हैं। यह रिकॉर्डेड टेप पिछले दो दिनों में कई मतदाताओं के मोबाइल पर भेजा गया है, जिससे शहर में इसकी चर्चाएँ तेज हैं।

यवतमाळ नगर परिषद के लिए 20 दिसंबर 2025 को मतदान तय है, और यह चुनाव भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट) तथा कांग्रेस समेत कई दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गया है। भाजपा की तरफ से एडवोकेट प्रियदर्शनी उईके नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं, जिनके समर्थन में फडणवीस ने कॉल के माध्यम से मतदाताओं से उनके नाम पर वोट देने की अपील की। स्थानीय स्तर पर यह संदेश व्यापक रूप से फैलाया जा रहा है और इसे चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा ने प्रचार के अंतिम चरण में इस डिजिटल विधि का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं तक सीधा संदेश पहुँचाने की कोशिश की है, ताकि पार्टी को यवतमाळ में सियासी वर्चस्व बनाए रखने में मदद मिले। इसके अलावा, स्थानीय रोडशो और सेलिब्रिटी कार्यक्रमों के साथ यह कॉल प्रचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

यह कदम चुनावी रणनीति में नई तकनीकों के इस्तेमाल का उदाहरण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल अब प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संवाद के अद्यतन तरीकों को अपनाकर मतदाताओं पर प्रभाव डालने के प्रयास में हैं।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर

नंदिग्राम टाईम्स
RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD
Saturday 20th December 2025 वर्ष - 9, अंक 234 , पृष्ठ 04

महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव 2025: नांदेड और लातूर में पिछले चुनावों का हाल

महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव 2025 के मतगणना के लिए तैयारियाँ चल रही हैं, जिनमें नांदेड और लातूर जिलों में भी पिछले स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम पर ध्यान है। मतगणना 21 दिसंबर को होने वाली है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

नांदेड जिले में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों के लिए उम्मीदवारों ने अपनी-अपनी तैयारी पूरी कर ली है और परिणामों का इंतज़ार है। इसमें कई वार्डों में प्रतिस्पर्धा कड़ी रही है और मतदाता काफी सक्रिय दिखे हैं।

लातूर जिले में भी नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए परिणाम घोषणा से पहले मतगणना की पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लातूर के कई नगर परिषदों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला संतुलित रहा है और मतगणना के बाद ही विजेताओं का फैसला होगा। कुल मिलाकर इन दोनों जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों का परिणाम 21 दिसंबर को आयेंगा और इससे स्थानीय राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

नांदेड़ निकाय चुनाव में 'लाड़ली बहनों' की बढ़त: कुछ वार्डों में महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा

नांदेड़ | 19 दिसम्बर 2025: नांदेड़ महानगरपालिका के आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 5,01,799 मतदाता पंजीकृत हैं। इसमें 2,54,999 पुरुष, 2,46,696 महिलाएँ, और 104 अन्य मतदाता शामिल हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर पुरुष मतदाता संख्या में थोड़ी आगे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वार्डों में महिला मतदाता संख्या में पुरुषों से अधिक हैं।

मतदाता डेटा के अनुसार 20 वार्डों में से केवल कुछ विशेष वार्डों में ही महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक पाई गई है। ऐसे प्रमुख वार्डों में शामिल हैं:

* वार्ड 2 (तरोडा बु. क्षेत्र) जहां महिलाओं (13,743) की संख्या पुरुषों (13,458) से ज़्यादा है।
* वार्ड 9 (नवा मोंढा क्षेत्र) में भी महिलाएं (11,962) पुरुषों (10,969) से आगे हैं।

* वार्ड 18 (खड़कपुरा/देगांवचाल क्षेत्र) में महिलाओं की संख्या (13,067) पुरुषों (12,972) से अधिक बताई गई है।

बाकी वार्डों में पुरुष मतदाता अभी भी संख्या के हिसाब से अधिक हैं, जैसे कि CIDCO/वाघाला वार्ड (वॉड 20) में पुरुष मतदाताओं की संख्या 16,100 है जबकि महिलाएं 15,808 हैं। विश्लेषण से यह भी सामने आया है कि कुछ वार्डों में तीसरे-लिंग (Other) मतदाता भी दर्ज हैं, जैसे साँगवी बु. और शिवाजीनगर वार्डों में, जो स्थानीय जनसांख्यिकीय विविधता को दर्शाते हैं। इस चुनाव में बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू की गई है, जिसमें अधिकांश वार्डों से चार-चार निगम पार्षद चुने जाएंगे, सिवाय CIDCO/वाघाला के जहाँ पाँच पार्षदों का चुनाव होगा। चुनाव की तैयारियाँ और प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। देरी के बावजूद, पिछले 2017 के चुनाव के बाद से लगभग तीन वर्षों के इंतजार के बाद, जनता, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद पार्टियों ने विशेष वार्ड रणनीतियाँ तैयार करना शुरू कर दिया है, खास कर उन वार्डों में जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, क्योंकि इन वार्डों में महिला मतदाताओं का समर्थन जीत की दौड़ को प्रभावित कर सकता है।

स्थानीय निवासी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार के चुनावों में महिला मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी से नगर निगम के विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं के समाधान में सुधार होगा।

अब बिना तलाठी हस्ताक्षर 15 रुपये में मिलेगा 'सातबारा' उतारा

नांदेड : राज्य के किसानों और जमीनधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त सातबारा, 8-अ और फेरफार उतारों को पूरी तरह कानूनी मान्यता दे दी है। अब इन दस्तावेजों पर तलाठी की प्रत्यक्ष सही और कार्यालय की मुहर की आवश्यकता नहीं रहेगी। 'डिजिटल सातबारा महाभूमी अभिलेख' पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक कहीं से भी मात्र 15 रुपये शुल्क देकर अधिकृत उतारा डाउनलोड कर सकता है। इन उतारों पर क्यूआर कोड आधारित सत्यापन सुविधा उपलब्ध है, जिससे उनकी प्रामाणिकता तुरंत जांची जा सकती है। यह डिजिटल उतारा बैंक ऋण, पीक लोन, सरकारी योजनाओं, भूमि खरीद-फरोख्त, फेरफार, वारस नोंद और न्यायालयीन कार्यों के लिए पूरी तरह वैध होगा। इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को बार-बार तलाठी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

नांदेड: आगामी स्थानीय चुनावों से पहले शिवसेना (शिंदे गुट) के भीतर तालमेल की कमी उजागर हो गई है, जहाँ दो बड़े विधायक बालाजी कल्याणकर और हेमंत पाटिल चुनावी गठबंधन को लेकर अलग-अलग राय रख रहे हैं।

नांदेड में शिंदे सेना के आमदारों में तालमेल की कमी, युती के एजेंडे पर मतभेद उभरे

मामले की शुरूआत तब सामने आई जब शिंदे गुट की ओर से भाजपा के साथ गठबंधन को प्राथमिकता देने की बात कही गई, लेकिन पार्टी के ही एक अन्य नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राष्ट्रवादी/एनसीपी) के साथ तालमेल की पैरवी कर रहे हैं, जिससे घमासान खड़ा हो गया है।

शिंदे सेना के नांदेड उत्तर से विधायक बालाजी कल्याणकर का कहना है कि आगामी स्थानीय चुनावों में भाजपा के साथ युती करना सबसे सही रणनीति होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश के तहत भाजपा से सीट-वाटपूर्वक गठबंधन की प्राथमिक चर्चा हो चुकी है और यदि सहयोगी तैयार है, तो 60-40 के बंटवारे के रूप में सीटें बाँटी जा सकती हैं।

दूसरी ओर, शिंदे सेना के नेता विधायक नामदार हेमंत पाटिल की राय बिल्कुल अलग है। उन्होंने राष्ट्रवादी एनसीपी के विधायक प्रतापराव चिखलीकर से मुलाकात की और एनसीपी के साथ गठबंधन के संकेत भी दिए। पाटिल का मानना है कि पिछली 40 वर्षों के अनुभवों के आधार पर भाजपा नेतृत्व निश्चित रूप से गठबंधन को आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए उन्हें राष्ट्रवादी के साथ जमकर भूमिका निभानी चाहिए।

इन विरोधाभासी क्रियाओं से शिंदे सेना के भीतर समन्वय की कमी और रणनीति में असहमति के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी इस पर गहमागहमी दिखाई दे रही है, जिससे नांदेड की राजनीति में आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि शिंदे सेना के नेताओं के बीच यह मतभेद जारी रहा, तो भाजपा तथा अन्य सहयोगियों के साथ महायुति गठबंधन की स्थिति प्रभावित हो सकती है और नांदेड चुनाव के नतीजों पर इसका सीधा असर दिख सकता है।

नांदेड में 40 कांग्रेस पार्षदों का भाजपा में ज्वाइन, चुनावी समीकरण में बड़ा बदलाव?

नांदेड: आगामी नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरम है, जहाँ कांग्रेस ने 2017 में 81 में से 73 सीटें जीतकर स्पष्ट जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उसी कांग्रेस के 40 पूर्व नगरसेवक भाजपा के दामन में शामिल हो गए हैं। इनमें माजी महापौर, उपमहापौर और सभापति जैसे अनुभवी नेता शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोडकर अब भाजपा के कमल चिन्ह को अपनाया है। इससे न सिर्फ भाजपा के संख्याबल में वृद्धि हुई है बल्कि अनुभव का भंडार भी बढ़ा है।

राजनीय विश्लेषकों का कहना है कि यह बदलाव कांग्रेस के लिए चिंताजनक संकेत है, खासकर तब जब अशोकराव चव्हाण के नेतृत्व में पहले कांग्रेस ने मुस्लिम, दलित और वंचित समाज को साथ लेकर स्थानीय राजनीति में मजबूत गठबंधन बनाया था।

इन पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या मतदाता भी अपनी निष्ठा बदलेंगे? मतदाताओं के मन में विश्वासघात और पार्टी निष्ठा को लेकर संदेह है, जो चुनाव परिणाम पर असर डाल सकता है। कांग्रेस की जिम्मेदारी अब विद्यमान खासदार रवींद्र चव्हाण के कंधों पर है, जिन्हें यह देखना होगा कि क्या अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक अब भी पार्टी के साथ है या नहीं।

वहीं भाजपा के सामने यह चुनौती है कि वह 'जुने-नये' नेताओं को एकजुट करके एक मजबूत उम्मीदवार सूची पेश करे ताकि पार्षदों के अनुभव और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन बैठ सके। विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय चुनावों में उमेदवार की व्यक्तिगत छवि, विकास कार्यों का प्रभाव और स्थानीय संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पार्टी निष्ठा और विश्वासघात के सवाल मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में नांदेड की राजनीतिक तस्वीर आगामी मतदान तक और अधिक स्पष्ट होगी।

नांदेड महापालिका निवडणूक: उपमुख्यमंत्री शिंदे के निकटवर्ती मीनल पाटील प्रभाग ३ में उतरे, राजकीय घमासान तेज

नांदेड | नांदेड महानगरपालिका चुनावों की घोषणा के बाद शहर में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं उम्मीदवारों की पसंद पर भी राजनीतिक नजरें टिक गई हैं। इसी बीच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी गजानन पाटील ने अपनी पत्नी मीनल पाटील को महापालिका चुनाव में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है।

गजानन पाटील मूल रूप से भोकर तालुका के निवासी हैं। मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने जनकल्याण कक्ष की स्थापना की थी, जिसका नेतृत्व गजानन पाटील ने किया। इस कक्ष के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाई जाती थी।

इसी दौरान गजानन पाटील की उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे के साथ नजदीकियां बढ़ीं। अब वे अपनी पत्नी मीनल पाटील को प्रभाग संख्या 3, सांगवी प्रभाग से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। मीनल पाटील उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर हैं और यह उनके लिए पहला चुनाव होगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से संपर्क बढ़ाना और नागरिकों की समस्याओं को समझ कर प्रचार रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। उनकी इस कोशिश के पीछे उपमुख्यमंत्री और सांसद के करीबी होने का राजनीतिक सहारा भी नजर आ रहा है।

इससे पहले भी एकनाथ शिंदे के निकटवर्ती बालाजी खतगावकर ने मुखेड विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक तुषार राठोड के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब शिंदे के करीबी की महापालिका चुनाव में एंट्री ने राजनीतिक हलचल और चर्चाओं को बढ़ा दिया है।

नांदेड महानगरपालिका चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं। 20 प्रभागों में 81 सीटों के लिए बीजेपी के पास 450 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन की मांग की है। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना (शिंदे और ठाकरे गुट), कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस बार उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया सभी दलों के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है और नामांकन को लेकर राजनीतिक नाटक भी देखने को मिल सकता है।

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़–431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)